



सत्यमेव जयते

आयुक्त का कार्यालय
Office of the Commissioner
केंद्रीय जीएसटी, अपील अहमदाबाद आयुक्तालय
Central GST, Appeals Ahmedabad Commissionerate
जीएसटी भवन, राजस्व मार्ग, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद-380015
GST Bhavan, Ambawadi, Ahmedabad-380015
Phone: 079-26305065 - Fax: 079-26305136
E-Mail : commrappl1-cexamd@nic.in
Website : www.cgstappealahmedabad.gov.in

आजादी का
अमृत महोत्सव**By Regd. Post**

DIN No.: 20230164SW0000777D2E

(क)	फ़ाइल संख्या / File No.	GAPPL/COM/STP/2382/2022-APPEAL / 6830-35
(ख)	अपील आदेश संख्या और दिनांक / Order-In-Appeal No. and Date	AHM-EXCUS-003-APP-083/2022-23 and 24.12.2022
(ग)	पारित किया गया / Passed By	श्री अखिलेश कुमार, आयुक्त (अपील) Shri Akhilesh Kumar, Commissioner (Appeals).
(घ)	जारी करने की दिनांक / Date of issue	02.01.2023
(ङ)	Arising out of Order-In-Original No. AC/S.R./37/ST/Kadi/2021-22 dated 31.03.2022 passed by the Assistant Commissioner, CGST & CE, Division-Kadi, Gandhinagar Commissionerate	
(च)	अपीलकर्ता का नाम और पता / Name and Address of the Appellant	M/s Pareshbhai P. Prajapati, A/19, Suvarna Palace, Karannagar Road, Kadi, Gujarat-382715

कोई व्यक्ति इस अपील-आदेश से असंतोश अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील अथवा पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि ऐसे आदेश के विरुद्ध हो सकता है।

Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way.

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन:-

Revision application to Government of India:

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली: 110001 को की जानी चाहिए :-

A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :-

- (क) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानिकार खाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a Warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course



of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

(घ) अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं 2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतरमूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ का मुख्य शीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(3) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम होती रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्नरकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

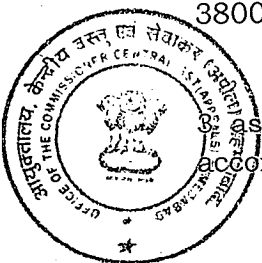
सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-
Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(2) उक्तलिखित परिच्छेद में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में 2nd माला, बहुमाली भवन, असरवा, गिरधरनागर, अहमदाबाद-380004।

To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2nd floor, Bahumali Bhawan, Asarwa, Girdhar Nagar, Ahmedabad: 380004. In case of appeals other than as mentioned above para.

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of



Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची -1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूलआदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रतिपर रू 6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) एके प्रति अपीलों के मामले में कर्तव्यमांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के अंतर्गत, शामिल होगा कर्तव्य की मांग (Duty Demanded)।

- (1) खंड (Section) 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (2) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (3) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि।

यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में 'अपील' दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।

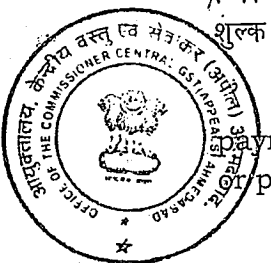
For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994).

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

(6)(i) इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो मांग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



अपीलिय आदेश / ORDER-IN-APPEAL

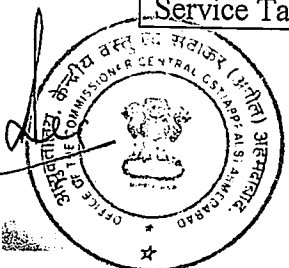
The present appeal has been filed by M/s Pareshbhai Popatlal Prajapati, 8-Ashadeep Society, Detroj Road, Kadi, Gujarat (address as per appeal memorandum : A/19, Suvarna Palace, Karannagar Road, Kadi, Gujarat-382715) [hereinafter referred to as "*the appellant*"] against Order in Original No. AC/S.R./37/ST/Kadi/2021-22 dated 31.03.2022 [hereinafter referred to as "*impugned order*"] passed by the Assistant Commissioner, Central GST, Division - Kadi, Commissionerate : Gandhinagar [hereinafter referred to as "*adjudicating authority*"]. The appellant are holding PAN No. AVQPP5807K and were not registered with the Service Tax department.

2. Briefly stated, the facts of the case is that as per the data received from the Income Tax department, for the period F.Y.2015-16, it was observed that the gross value of Sale of Services declared by the appellant was above the Service Tax exemption limit of Rs.10 lakhs in terms of Notification No.33/2012-ST dated 20.06.2012. In order to verify the observed discrepancies, the appellant were requested vide letters/e-mails dated 28.07.2020 and 18.08.2020 to provide documents viz. Balance Sheet, Profit & Loss Account, Income Tax Returns, Form 26AS, Service Income and Service Tax Ledger for the F.Y. 2015-16. However, the appellant did not respond. The activities undertaken by the appellant was considered to be covered under the definition of 'Service' under Section 66 B (44) of the Finance Act,1994.

2.1 Considering the value of Services declared in the ITR/TDS filed by the appellant for the F.Y.2015-16 the Service tax liability of the appellant was determined at Rs.1,48,709/- as per the table below :

Table

Value of Sale of Services (ITR)	Rs.10,25,575/-
Total Amount paid credited under Section 194C of the Income Tax Act,1961	0/-
Total Amount paid credited under Section 194H of the Income Tax Act,1961	0/-
Total Amount paid credited under Section 194Ia & Ib of the Income Tax Act,1961	0/-
Total Amount paid credited under Section 194J of the Income Tax Act,1961	0/-
Higher value of Sale of Services in ITR & TDS	Rs.10,25,575/-
Service Tax payable @ 14.5%	Rs.1,48,709/-



2.1. The appellant was issued a Show Cause Notice No. GEXCOM/ADJN/ST/309/2020-CGST-DIV-KADI-COMMRTE-GANDHINAGAR dated 30.09.2020 (in short SCN) for demand and recovery of Service Tax amounting to Rs.1,48,709/- under proviso to sub-section (1) of Section 73 of the Finance Act, 1994 read with Section 68 of the Finance Act, 1994 along with interest under Section 75 of the Act. The SCN also proposed imposition of penalties under Sections 70, 77 and 78 of the Finance Act, 1994.

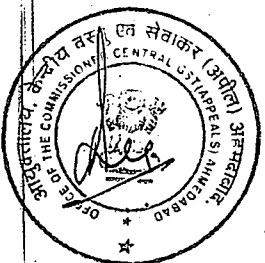
3. The SCN was adjudicated by the adjudicating authority vide the impugned order wherein :

- (i) The demand of service tax amounting to Rs. 1,48,709/- was confirmed under proviso to sub-section (1) of Section 73 of the Finance Act, 1994 read with Section 68 of the Finance Act, 1994 along with interest under Section 75 of the Finance Act, 1994.
- (ii) Penalty amounting to Rs. 1,48,709/- was imposed under Section 78 of the Finance Act, 1994.
- (iii) Penalty amounting to Rs.10,000/- was imposed under Section 77 of the Finance Act, 1994.
- (iv) Penalty amounting to Rs.40,000/- was imposed under Section 70 of the Finance Act, 1994.

4. Being aggrieved with the impugned order, the appellant have filed the present appeal on merits as well as with an application for condonation of delay. In support of their application for condonation of delay, they have relied on the decision of the Hon'ble Supreme Court of India in the case of Stae of U.P Vs. Harish Chandra – 1996 (85) ELT 209 (SC).

5. Personal Hearing in the case was held on 08.12.2022, Shri Gunjan Shah, Chartered Accountant, appeared on behalf of the appellant for the hearing. He again re-iterated the submissions made in application for condonation of delay.

6. I have gone through the facts of the case, submissions made in the Appeal Memorandum, submissions made in the application for condonation of delay and submissions made during personal hearing.



7. As regards the application for condonation of delay, it is observed from the records that the present appeal was filed by the appellant on 19.07.2022 against the impugned order dated 31.03.2022, which the appellant claimed to have received on 22.04.2022. Therefore, the period of two months for filing the appeal before the Commissioner (Appeals) ended on 22.06.2022. However, this appeal was filed on 19.07.2022 i.e after 27 days of expiry of the period of 2 months.

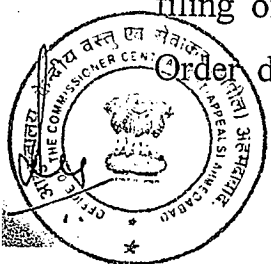
8. It is also observed that the Appeals preferred before the Commissioner (Appeals) are governed by the provisions of Section 85 of the Finance Act, 1994. The relevant part of the said section is reproduced below :

“(3A) An appeal shall be presented within two months from the date of receipt of the decision or order of such adjudicating authority, made on and after the Finance Bill, 2012 received the assent of the President, relating to service tax, interest or penalty under this Chapter:

Provided that the Commissioner of Central Excise (Appeals) may, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of two months, allow it to be presented within a further period of one month.”

9. Considering the prevailing Covid-19 pandemic, the Hon'ble Supreme Court of India vide Order dated 23.03.2020 extended the period of limitation in all proceedings w.e.f. 15.03.2020. The relaxation of the period of limitation was subsequently extended till 02.10.2021 vide Order dated 23.09.2021. Subsequently, the Hon'ble Supreme Court of India vide Order dated 10.01.2022 directed that the period from 15.03.2020 till 28.02.2022 shall stand excluded for the purposes of limitation. It was further directed by the Hon'ble Supreme Court that where the limitation would have expired during the period from 15.03.2020 till 28.02.2022, notwithstanding the actual balance period of limitation remaining, all persons shall have a limitation period of 90 days from 01.03.2022. In the event the actual balance period of limitation remaining with effect from 01.03.2022 is greater than 90 days, that longer period shall apply.

10. In the instant case, the impugned order was issued on 31.03.2022 and admittedly the appellant had received it on 22.04.2022. Therefore, the relaxation in filing of appeals, extended by the Order Hon'ble Supreme Court of India vide Order dated 10.01.2022, would not be applicable to them. Further, the present

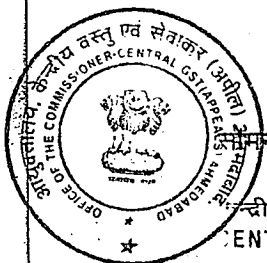


appeal was filed by the appellant on 19.07.2022 i.e after a period of more than two months of receipt of the impugned order. It has been contended that delay had occurred due to obtaining of copies of work orders from GWSSB, a government department. However, I find that the contentions of the appellant are vague and without merits as the work orders, under which they had undertaken performance of services from government department, should be available with them. Further, no documents or correspondence with GWSSB have been submitted, Hence, I find that the reasons for delay in filing this appeal, cited by the appellant in their application, are vague and not found to be convincing and cogent and do not fall under the category of appropriate cause/reason for condonation of delay. I have gone through the judgement of Hon'ble Supreme Court of India in the case of State of U.P. Vs Harish Chander – 1996 (85) ELT 209 (SC). I find that the Hon'ble Supreme Court has subsequently in the case of the Chief Post Master General Vs Living Media India Ltd.-2012(277) ELT 289 (SC) distinguished this case. Further, in this case the appellant has not been able to explain the delay in filing appeal with cogent reasons/documents. Hence, their contentions are rejected.

11. In terms of proviso to Section 85 (3A) of the Finance Act, 1994, the Commissioner (Appeals) is allowed to condone delay and allow a further period of one month, beyond the two month period only upon sufficient cause being shown to substantiate the delay, which the appellant have failed to explain in the instant case. The present appeal filed on 19.07.2022, is, therefore, clearly barred by limitation. In the absence of any appropriate/sufficient/cogent/convincing reason for delay in filing appeal, this authority does not find it a fit case to exercise the powers to condone delay in filing of appeal as per the proviso to Section 85 (3A) of the Finance Act, 1994.

12. In view of the facts discussed herein above without delving into the merits of the case, the appeal filed by the appellant is hereby rejected on the grounds of limitation.

13. ~~अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।~~
The appeal filed by the appellant stands disposed of in above terms.



attested

Attested
श्रीमान्थ अक्षय कुमार चौधरी
अधीक्षक/SUPERINTENDENT
द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (अपील), अहमदाबाद.
CENTRAL GST (APPEALS), AHMEDABAD.

(Akhilesh Kumar)
22nd December 2022

Commissioner (Appeals)
Date: 22nd December, 2022

BY RPAD / SPEED POST

To

M/s Pareshbhai Popatlal Prajapati,
8-Ashadeep Society,
Detroj Road, Kadi, Gujarat

M/s Pareshbhai Popatlal Prajapati,
A/19, Suvarna Palace,
Karannagar Road,
Kadi, Gujarat-382715

Copy to:

1. The Chief Commissioner, Central GST, Ahmedabad Zone.
2. The Principal Commissioner, CGST, Commissionerate - Gandhinagar.
3. The Assistant Commissioner, Central GST Division - Kadi,
Commissionerate : Gandhinagar.
4. The Assistant Commissioner (System), CGST, Appeals, Ahmedabad. (for
uploading the OIA)
- ✓ 5. Guard File.
6. P.A. File.

